भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 523
मंगलवार, 06 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण

†523. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है और पीएसीएस के डिजिटलीकरण की योजना/परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;
(ख) क्या पीएसीएस सामान्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के साझा सॉफ्टवेयर और प्लेटफार्म के अंतर्गत डिजिटलीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी आधारित (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है ।

अब तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 62,318 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिसके लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के तौर पर 488.42 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है । इस परियोजना के लिए नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर के कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास किया जा चुका है, और अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 15,783 पैक्स ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं । राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद और लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है । अनुमोदित पैक्स, ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए पैक्स और उन्हें जारी भारत सरकार के हिस्से की धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है ।

इस परियोजना के अधीन पैक्स स्तर पर कॉमन अकाउंटिग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित हो सकेगा और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी । इससे किसानों के बीच पैक्स कार्यकरण के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी जो फलत: "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी ।

*****

अनुबंध

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स की सं.	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए पैक्स की सं.	वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जारी भारत सरकार के हिस्से की राशि (करोड़ रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	2,037	12	14.93
2	अरुणाचल प्रदेश	14	14	0.21
3	असम	583	562	6.41
4	बिहार	4,495	2,626	32.95
5	छत्तीसगढ़	2,028	64	14.86
6	गोवा	58	12	0.32
7	हरियाणा	711	100	4.85
8	हिमाचल प्रदेश	870	634	13.22
9	झारखंड	1,500	1,275	10.99
10	कर्नाटक	5,491	13	40.25
11	मध्य प्रदेश	4,534	2,557	45.94
12	महराष्ट्र	12,000	2,440	87.95
13	मणिपुर	232	-	2.55
14	मेघालय	112	27	1.23
15	मिज़ोरम	25	23	0.27
16	नागालैंड	33	33	0.50
17	पंजाब	3,482	20	25.52
18	राजस्थान	5,585	1,170	43.81
19	सिक्किम	107	107	1.63
20	तमिलनाडु	4,532	19	33.2
21	त्रिपुरा	268	128	2.95
22	उत्तर प्रदेश	3,062	1,539	24.68
23	पश्चिम बंगाल	4,167	15	30.54
24	गुजरात	5,754	1,949	42.17
25	जम्मू और कश्मीर	537	351	5.25
26	पुड्डुचेरी	45	37	0.60
27	अंडमान और निकोबार	46	46	0.52
28	लद्दाख	10	10	0.12
कुल		**62,318**	**15,783**	**488.42**

*****